रोक्षन्न शर्मा

बनाम

अरुण शर्मा

(सिविल अपील संख्या 1966/2015)

17 फरवरी, 2015

[न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन और न्यायाधिपति सी. नागप्पन]

हिंदू अवयस्क और संरक्षकता अधिनियम, 1956– धारा 6

बच्चे की अभिरक्षा - माता-पिता के परस्पर विरोधी दावे – विचारण न्यायालय , गोवा द्वारा नाबालिग बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा माँ को दी गई जबकि पिता को मुलाक़ात का अधिकार दिया गया - हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को पलट दिया - माँ को सप्ताह में 3 दिन लगातार मुलाक़ात का अधिकार दिया गया - इस बीच , पिता बिना सूचना के मुंबई चले गए - माँ द्वारा चुनौती - निपटान, माँ को बच्चे से मिलने की अनुमति, हालाँकि, गोवा अदालत में कार्यवाही लंबित होने के कारण, पिछले आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया - इसके बाद, माँ द्वारा मुलाक़ात के अधिकार के लिए आवेदन दायर किया गया गोवा - विचारण न्यायालय ने तीन दिनों के लिए सप्ताहांत मुलाक़ात का अधिकार दिया, बच्चे को अदालत से ले जाया जाएगा - हालाँकि, दूसरे एकल न्यायाधीश ने कहा कि 'बार-बार' निरंतर नहीं हो सकता है और बच्चा तीन दिनों के लिए विशेष रूप से अपनी माँ के साथ नहीं रहेगा - अपील पर, आयोजित किया गया : जहां बच्चा पांच साल की उम्र से नीचे है वहां पिता की अभिरक्षा की उपयुक्तता प्रासंगिक नहीं है मां शिशु की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त होती है - पिता को दलील देनी होती है और मां की अनुपयुक्तता को साबित करना होता है - तथ्यों के आधार पर, दूसरे एकल न्यायाधीश ने एक समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्देशों को

रद्द करने में गलती की, जिसके परिणामस्वरूप न्याय के गर्भपात में - 1890 अधिनियम की धारा 14 नाबालिग से संबंधित संरक्षकता या हिरासत विवादों से निपटने के लिए केवल एक अदालत की हितकारी आवश्यकता को स्वीकार करती है - ऐसे मामले में, माता-पिता के कोई अधिकार नहीं हैं जिन्हें लागू करना होगा; बच्चे का कल्याण मुख्य है - समन्वय पीठों को पूर्व आदेशों का सम्मान करना चाहिए - फोरमशॉपिंग या कोर्टशॉपिंग से सख्ती से निपटा जाना चाहिए - इसके अलावा, पिता को गोवा अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए था जो माता-पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था - इस प्रकार, अस्थायी हिरासत बच्चा माँ को दिया गया और मुलाक़ात का अधिकार पिता को दिया गया- संरक्षकता और वार्ड अधिनियम, 1890- धारा 4(2), 26, 14

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 पिता की अभिरक्षा के लिए उपयुक्तता प्रासंगिक नहीं है, जहां जिस बच्चे की अभिरक्षा को लेकर विवाद है, वह पांच साल से कम उम्र का है, क्योंकि मां उसकी नाजुक उम्र के दौरान शिशु की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त है। चूंकि बच्चा पांच साल से कम उम्र का है, इसलिए यह पिता पर निर्भर करता है कि वह मां से निवेदन करे और उसे साबित करे कि वह उपयुक्त नहीं है। इन विचारों में पिता का चरित्र और पृष्ठभूमि भी प्रासंगिक हो जाएगी, लेकिन केवल एक बार अदालत को माँ की उपयुक्तता पर दृढ़ता और दृढ़ता से संदेह होगा; केवल तभी और तब भी माता-पिता की तुलनात्मक विशेषताएँ चलन में आएँगी। इस दृष्टिकोण को एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं अपनाया गया, जबकि सिविल न्यायाधीश द्वारा इसे उचित रूप से अपनाया गया है। [पैरा 13] [586-एच; 587-ए-सी]

1.2 बेवजह, दूसरे एकल न्यायाधीश ने मां को सप्ताहांत में मुलाकात की अनुमति देने के आदेश में गलती पाई, इस वास्तविकता को नजरअंदाज करते हुए कि विचारण न्यायालय केवल पिछले एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू कर रहा था। जब पिता के खिलाफ मामला समाप्त हो गया, जिसने पिछले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी, तो बच्चे के कल्याण के सवाल पर नए सिरे से विचार करना विचारण न्यायालय के लिए खुला नहीं था। विचारण न्यायालय से बस इतना ही अपेक्षित था कि वह मां के लिए तीन दिन की अभिरक्षा आवंटित करेगी। वास्तव में दूसरा एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के पिछले आदेश को अपनी समझ और अर्थ दिया, जो पिछली रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई बातों के बिल्कुल विपरीत है। आदेश की व्याख्या करते हुए, एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर "अधिमानतः" शब्द जोड़ा, लेकिन पिछले आदेश में "अधिमानतः" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आक्षेपित आदेश इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ करता प्रतीत होता है कि सभी तीन व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे और हाल ही में गोवा में स्थानांतरित हुए हैं, जो उस समय, पार्टियों का एकमात्र निवास स्थान था। इसमें मां की इस बात को भी उचित महत्व नहीं दिया गया है कि उन्होंने अपनी बचत गोवा के साथ-साथ मुंबई में संयुक्त नाम से संपत्ति खरीदने में निवेश की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिता संतोषजनक ढंग से यह नहीं दिखा सके कि उनकी कोई आय थी, प्रथम दृष्टया, माँ का बयान विश्वसनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पिता ही थे जिन्होंने गोवा में कार्यवाही शुरू की थी, जिसके अधिकार क्षेत्र का मां ने विरोध नहीं किया है और इसलिए, शुरुआती चरणों में मां के खिलाफ कार्यवाही करना न तो न्यायसंगत है और न ही उचित है, क्योंकि लंबी मुकदमेबाजी पहले ही दोनों पक्षों के बीच चल चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे एकल न्यायाधीश ने मुद्दों पर निर्णय न

लेने में लापरवाही बरती और इसके बजाय केवल नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उसके समक्ष दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। पहले एक समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्देशों को रद्द कर दिया गया है और न्याय की हत्या हुई है। [पैरा 15] [588-ई-एच;589 ए-एफ]

1.3 उच्च न्यायालय के पिछले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना दूसरे एकल न्यायाधीश के लिए उचित नहीं था। जी एंड डब्ल्यू अधिनियम की धारा 14 नाबालिग से संबंधित संरक्षकता या हिरासत विवादों से निपटने में केवल एक अदालत की हितकारी आवश्यकता को स्वीकार करती है। इस याचिका में सिविल जज द्वारा पारित आदेश के स्वामित्व को चुनौती दी गई थी, जो बदले में उस आदेश के अनुपालन में था जिसमें अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर सप्ताह में कम से कम तीन दिन मां से मिलने का अधिकार दिया गया था। पक्षों के अशांत विवाह, बच्चे के आईवीएफ गर्भाधान आदि के इतिहास को प्रथम एकल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश द्वारा विधिवत नोट किया गया है। एकल न्यायाधीश ने तब गोवा राज्य में एचजीएम अधिनियम के साथ-साथ जी एंड डब्ल्यू अधिनियम की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया था, एक ऐसा पहलू जिस पर पहले की किसी भी कार्यवाही में माता या पिता द्वारा उत्तेजित नहीं किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अदालत को हिरासत के विरोधाभासी दावों का सामना करना पड़ता है तो माता-पिता के कोई अधिकार नहीं होते हैं जिन्हें लागू करना पड़ता है; बच्चा कोई वस्तु या गेंद नहीं है जिसे माता-पिता इधर-उधर उछालते रहें। केवल बच्चे का कल्याण ही विचार का केन्द्र बिन्दु है। संसद का यह सोचना सही है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः मां के पास होनी चाहिए और इस अपेक्षा से केवल मजबूत कारणों से ही इनकार किया जा सकता है। निर्णय में निरंतरता की आवश्यकता के कारण दूसरे एकल न्यायाधीश को अपने भाई न्यायाधीश की तुलना में खुद को अलग कर लेना चाहिए था,

जिन्होंने पिछली रिट याचिका पर निर्णय दिया था। [पैरा 16] [589-जी-एच; 590-ए-एफ]

1.4 पिता के बारे में गंभीर टिप्पणी की गई है, जिसने सिविल जज को सूचित किए बिना या अनुमति लिए बिना, बच्चे के साथ उसके अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है और यह न्यायालय की अवमानना के समान भी हो सकता है। जी एंड डब्ल्यूएक्ट की धारा 26 का उल्लंघन किया गया है और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। स्थानांतरण अब एक प्रसिद्ध कानूनी अवधारणा है क्योंकि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य या यहां तक कि एक देश से दूसरे देश में जाना अब दुर्लभ नहीं रह गया है। अक्सर यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि बच्चे की देखरेख करने वाले माता-पिता को कहीं और अधिक उपयुक्त रोजगार मिल जाता है। इसलिए, पीछे छूट गए पति या पत्नी के अधिकार की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। माँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होना चाह सकती है जहाँ उसे पिता की तुलना में बहुत लाभप्रद रूप से नियोजित किया जा सकता है जो किसी भी आय या नियमित आय के स्रोत का खुलासा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन मौजूदा मामले में, पिता को गोवा में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए था, जो माता-पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। ऐसा लगता है कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इसके बजाय एकल न्यायाधीश ने अनधिकृत स्थानांतरण को प्राथमिकता दे दी। आपराधिक याचिकाकर्ता का निपटारा मां को बच्चे से मिलने की अनुमति देकर किया गया था, लेकिन गोवा में कार्यवाही की लंबितता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने गोवा में अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश में हस्तक्षेप या परिवर्तन या संशोधन नहीं किया। फ़ोरम शॉपिंग या कोर्ट शॉपिंग से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। दूसरे एकल न्यायाधीश को यह ध्यान में रखना चाहिए

था कि यह पिता ही थे जिन्होंने गोवा में कार्यवाही शुरू की थी, जहां उस समय मां भी रह रही थी, प्रथम दृष्टया, उन्हें कैलफोर्निया में अपना रोजगार छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, ताकि वे इस स्थिति में आ सकें। अपने नवजात बेटे की देखभाल के लिए को-ऑर्डिनेट बेंच को पूर्व आदेशों का सम्मान करना चाहिए। [पैरा 17] [590-जी-एच; 591-ए-एफ]

1.5 तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। यह एक समन्वय पीठ के पिछले आदेश के अनुरूप नहीं है और वास्तव में इसके मुख्य निर्देशों को गंभीर रूप से रद्द कर देता है। अन्य विवादित आदेश को भी अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से खारिज कर दिया गया है कि यह शिशु की अस्थायी हिरासत के लिए उपयुक्तता दिखाने के लिए मां पर गलत तरीके से बोझ डालता है और इसलिए, एचएमजी अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिता द्वारा प्रस्तुत या रिकॉर्ड पर रखी गई किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि मां शिशु की देखभाल करने के लिए इतनी अयोग्य है कि एचएमजी अधिनियम की धारा 6 में वैधानिक धारणा से विचलन को उचित ठहराया जा सके। संक्षेप में बताए गए मुलाक़ात अधिकार हिरासत या अंतरिम हिरासत आदेशों से अलग हैं। अनिवार्य रूप से वे उस माता-पिता को सक्षम बनाते हैं जिनके पास अंतरिम हिरासत नहीं है, ताकि वे बच्चे को दूसरे माता-पिता की हिरासत से हटाए बिना उससे मिल सकें, यदि बच्चे को हिरासत में दिए गए माता-पिता से कई घंटे या यहां तक कि कुछ दिन दूर रहने की अनुमति है। अदालत द्वारा, बच्चे की अस्थायी हिरासत अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दी जाती है। [पैरा 18] [591-जी-एच; 592-ए-डी]

1.6 बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा अपीलकर्ता/माँ को हस्तांतरित कर दी जाती है और उन दोनों को दिए गए पते पर गोवा में रहने का निर्देश दिया जाता है।

प्रतिवादी/पिता के पास यहां दिए गए मुलाक़ात के अधिकार होंगे। उक्त आदेश अस्थायी प्रकृति के हैं। सिविल जज लंबित याचिका/आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय करेंगे। [पैरा 20] [592-एफ-एच]

सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा 2000 (1) एससीआर 915: (2000)3 एसईसी 14 - संदर्भित। मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली 2008 (8)एससीआर 260: (2008)7 एससीसी 673 - प्रतिष्ठित।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 10 वां संस्करण - संदर्भित।

वाद कानून संदर्भित

2000(1)एस सी आर 915	संदर्भित	पैरा 10
2008(8)एस सी आर 260	संदर्भित	पैरा 11

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 1966/2015

2014 की रिट याचिका संख्या 79 में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2014 से

के साथ

सी ए संख्या 1967/2015

कोलिन गोसालवेस, जुबली मोमलिया, सत्या मित्रा अपीलार्थी के लिए

मीनाक्षी अरोड़ा, राजेश कुमार, गौरव कुमार सिंह,राकेश चौरसिया, मित्तर एंड मित्तर कंपनी प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन

1. दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. 2014 की एसएलपी (सी) संख्या 31615 से उत्पन्न 2015 की सिविल अपील ने 2014 की रिट याचिका संख्या 79 में गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 अगस्त, 2014 के फैसले को चुनौती दी, जिसने बदले में 31.1.2014 को पारित आदेश पर सवाल उठाया। प्रतिवादी श्री अरुण शर्मा (इसके बाद 'पिता' के रूप में संदर्भित) द्वारा हमारे समक्ष 18.5.2013 को दायर वैवाहिक याचिका संख्या 15/2013/ii में मडगांव, गोवा में द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन (इसके बाद इसे सिविल जज के रूप में भी जाना जाता है) हिंदू अवयस्क और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत। इस याचिका में पिता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की है कि (ए) नाबालिग बच्चे, थलबीर शर्मा की कस्टडी उसके पास रखी जाए और (बी) अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से हमारे सामने अपीलकर्ता (बाद में मां के रूप में संदर्भित) को जबरन कब्जा करने से रोका जाए। आवेदक की हिरासत से नाबालिग बच्चे थलबीर की। ये कार्यवाही पिता के कहने पर शुरू की गई और गोवा में लंबित है; उस वक्त जब ये तीनों शख्स गोवा के रहने वाले थे. तथ्यों के साथ-साथ कानून की विस्तृत चर्चा के बाद, द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन मडगांव, गोवा ने आदेश दिया कि "योग्यता के आधार पर याचिका का अंतिम निपटान होने तक, प्रतिवादी रौक्सैन शर्मा को नाबालिग बच्चे थलबीर शर्मा की अंतरिम हिरासत दी जाती है। आवेदक के पास बच्चे से मिलने का अधिकार होगा। वह बच्चे से अपनी मुलाकात के बारे में प्रतिवादी को अग्रिम रूप से सूचित करेगा, जिसके बाद वह आवेदक को बच्चे से मिलने की अनुमति देगी। मां के साथ रहना चाहिए और इस तरह बच्चे के सर्वोपरि हितों की रक्षा और सुरक्षा की जाएगी; कि मां के पास हावर्ड विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी.सी. से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है और वह कैलिफोर्निया के लॉसएंजेल्स मिशन कॉलेज में एक स्थायी कॉलेज प्रोफेसर हैं; उनका आरोप है द्वि-ध्रुवीय विकार से पीड़ित

होने को दृढ़ता से साबित नहीं किया गया था और किसी भी स्थिति में, उसे अपने बेटे की हिरासत के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया था; कि पिता कथित तौर पर एक शराबी और नशीली दवाओं का आदी है जो एक दवा पुनर्वास क्लिनिक में शामिल हो गया था, और एक भी था नारकोटिक्स एनोनिमस (एन.ए.) के सदस्य; कि पिता की पहले शादी हो चुकी थी; और वह लाभकारी नौकरी पर नहीं थे। विवादित आदेश भी एक विस्तृत है जिसमें तथ्यों को नोट किया गया है और वैधानिक कानूनों के साथ-साथ मिसालों पर भी चर्चा की गई है

3. हालाँकि, विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से बिल्कुल भिन्न, गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि "इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि बच्चे के पालन-पोषण के लिए याचिकाकर्ता का प्यार भी आवश्यक है।" चूँकि प्रतिवादी जो माँ है, ऐसे बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में, हालाँकि अभिरक्षा याचिकाकर्ता के पास जारी रहेगी, फिर भी माँ होने के नाते प्रतिवादी को निश्चित रूप से नाबालिग बच्चे से बार-बार मिलने का अधिकार होगा। ऐसी मुलाक़ात अधिकार अस्थायी रूप से सप्ताह में कम से कम 3 दिनों के लिए होंगे। पक्षकार आपसी सहमति वाले स्थान पर, अधिमानतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर, विद्वान न्यायाधीश के समक्ष ऐसे दिन तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें तुरंत इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि अदालत गोवा में स्थित है, मुंबई में नहीं। ये निर्देश पिता के विरुद्ध अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं; माता कम से कम तीन दिनों के लिए और उतनी ही महत्वपूर्ण रूप से गोवा में मुलाकात के अधिकार की हकदार होतीं।

4. हमारे सामने, माँ ने बताया है कि अपने बेटे थलबीर की बहुत तलाश करने के बाद, उन्हें अगस्त, 2013 में पता चला कि पिता थलबीर के साथ मुंबई में थे। उन्होंने 2013 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 87 दायर की, जिसे 26.8.2013 के

आदेश द्वारा यह देखते हुए निपटा दिया गया कि हिंदू अवयस्क और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (एचएमजी अधिनियम) के तहत कार्यवाही गोवा में लंबित थी और निर्देश दिया गया कि मां को थलबीर तक पहुंच मिलनी चाहिए। मुंबई में पिता के निवास के निकट एक स्थान पर। इसके बाद, जैसा कि पहले ही 31.1.2014 को ऊपर उल्लेख किया गया है, वह आदेश जिसके द्वारा आक्षेपित आदेश में व्यवस्था को उलट दिया गया था, विद्वान सिविल न्यायाधीश , वरिष्ठ खंड, मडगांव द्वारा मां को हिरासत में रखने और गोवा में पिता से मुलाकात करने का आदेश दिया गया।

5. हम पहले सिद्धांतों पर संरक्षकता की कानूनी अवधारणा के आयात और आयाम पर विचार करेंगे। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के 5 वें संस्करण में गार्जियनशिप की परिभाषा शामिल है जो हमारे लिए उपयुक्त है। इसमें कहा गया है कि- "एक व्यक्ति ने कानूनी रूप से शक्ति के साथ निवेश किया है, और उस व्यक्ति की देखभाल करने और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति और अधिकारों का प्रबंधन करने का कर्तव्य सौंपा है, जिसे उम्र, समझ या आत्म-नियंत्रण के दोष के लिए माना जाता है अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ। वह व्यक्ति जिसके पास कानूनी रूप से किसी बच्चे के अवयस्क होने के दौरान उसके व्यक्ति, या संपत्ति या दोनों की देखभाल और प्रबंधन होता है" इसके बाद एक अभिभावक के बारह वर्गीकरण होते हैं लेकिन हम उनमें से केवल एक को ही पुन: प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लिखा है- "एक सामान्य अभिभावक वह होता है जिसके पास अपने संरक्षण के व्यक्ति और संपत्ति की सामान्य देखभाल और नियंत्रण होता है; जबकि एक विशेष अभिभावक वह होता है जिसके पास अपने संरक्षण के संबंध में विशेष या सीमित शक्तियां और कर्तव्य होते हैं, उदाहरण के लिए, एक अभिभावक जिसके पास हिरासत होती है संपत्ति का, लेकिन व्यक्ति का नहीं, या इसके विपरीत, या किसी अभिभावक आदिम का"। ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी 'कस्टडी' को किसी चीज़ या व्यक्ति की देखभाल और नियंत्रण के रूप में परिभाषित करती है। किसी चीज़

को रखना, रखवाली करना, देखभाल करना, निगरानी करना, निरीक्षण करना, परिरक्षण या सुरक्षा करना, अपने साथ उस चीज़ का विचार लेकर आना कि वह उस व्यक्ति की तत्काल व्यक्तिगत देखभाल और नियंत्रण में है जिसके संरक्षण में वह है। तत्काल प्रभार और नियंत्रण, न कि अंतिम, स्वामित्व का पूर्ण नियंत्रण, जिसका अर्थ हिरासत में रखी गई चीज़ की सुरक्षा और संरक्षण की ज़िम्मेदारी है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, दसवें संस्करण के संदर्भ में, 'विज़िटेशन' का अर्थ है एक गैर-संरक्षक माता-पिता की बच्चे तक पहुंच की अवधि। मुलाक़ात के अधिकार का अर्थ है एक गैर-संरक्षक माता-पिता या दादा-दादी के न्यायालय ने एक ऐसे बच्चे या पोते के साथ समय बिताने का विशेषाधिकार दिया है जो किसी अन्य व्यक्ति, आमतौर पर संरक्षक माता-पिता के साथ रह रहा है। मुलाक़ात आदेश का मतलब एक गैर-संरक्षक माता-पिता के लिए अपने बच्चों के साथ मुलाक़ात के समय को स्थापित करने वाला आदेश है। यद्यपि मुलाकात के दौरान गैर-संरक्षक माता-पिता बच्चे की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं, मुलाकात हिरासत से अलग होती है क्योंकि गैर-संरक्षक माता-पिता और बच्चा एक परिवार इकाई के रूप में एक साथ नहीं रहते हैं। हमारी राय में, मुलाक़ात अधिकारों का यह अर्थ बताया गया है - विघटन या हिरासत के मुकदमे में, घरेलू संबंधों के मामलों में माता-पिता को बच्चों से मिलने की अनुमति, अदालत के आदेश के तहत विवाह के बच्चों से मिलने का एक माता-पिता का अधिकार।

6. कई अन्य क़ानूनों में भी 'अभिभावक' की परिभाषाएँ शामिल हैं जैसे कि किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 जिसकी धारा 20 में कहा गया है कि - ""अभिभावक", एक बच्चे के संबंध में, उसका प्राकृतिक अभिभावक या कोई अन्य है वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान अभिभावक के रूप में मान्यता प्राप्त है।" चूंकि किशोर अधिनियम मुख्य रूप से किशोर के कल्याण से संबंधित

है, इसलिए संपत्ति के बजाय "व्यक्ति" पर जोर देना स्पष्ट और सही है। तमिलनाडु प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, 1994 अभिभावक शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है - "कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण या संरक्षण कानून या प्राकृतिक अधिकार या मान्यता प्राप्त उपयोग के द्वारा आता है, या जिसने देखभाल, पालन-पोषण स्वीकार या ग्रहण किया है किसी भी बच्चे की देखभाल या जिसे किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा किसी बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण या हिरासत सौंपी गई है।"

7. संरक्षकता व्यक्ति के साथ-साथ एक नाबालिग या एक की संपत्ति पर नियंत्रण रखती है और दूसरे की नहीं। यह अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 4 (2) में निहित परिभाषाओं को पढ़ने से स्पष्ट है। (जी एंड डब्ल्यूएक्ट) और एचएमजीएक्ट की धारा 4 (बी) जो स्पष्ट करती है कि "अभिभावक" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नाबालिग के व्यक्ति या उसकी संपत्ति या उसके व्यक्ति और संपत्ति दोनों की देखभाल करता है। धारा 9 नाबालिग के व्यक्ति की संरक्षकता के संबंध में एक आवेदन दाखिल करने पर विचार करती है और धारा 10 उस आवेदन के रूप को निर्दिष्ट करती है। धारा 12 नाबालिग की सुरक्षा और उसके व्यक्ति और संपत्ति की अंतरिम सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। धारा 14 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अवधि इंगित करती है कि इन विवादों का निर्णय धारा 10 की तर्ज पर एक अदालत द्वारा किया जाना चाहिए। सीपीसी जो प्रथम न्यायालय को क्षेत्राधिकार की प्राथमिकता प्रदान करती है। धारा 17 नाबालिग के कल्याण को प्रधानता देती है। उपधारा 2 अदालत को नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म, प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र और क्षमता और नाबालिग के रिश्तेदारों की निकटता पर उचित विचार करने का आदेश देती है। चूँकि थल्बिरिस बहुत ही कम उम्र का है, इसलिए उसकी इच्छाओं को निर्धारित करने की उपयुक्तता वर्तमान चरण में प्रासंगिक नहीं है; वह एक बुद्धिमान

संदर्भ बनाने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। धारा 25 एक वार्ड की हिरासत को उसके व्यक्ति के संरक्षक की हिरासत से हटाए जाने को कवर करती है, और यह बताती है कि यदि न्यायालय की राय है कि यह वार्ड के कल्याण के लिए होगा कि वह अपने अभिभावक की हिरासत में वापस आ जाए, तो वह उसकी वापसी का आदेश देगी।

8. धारा 26 का विशेष महत्व है कि यह न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति के संरक्षक पर भी वार्ड को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से हटाने पर सर्वव्यापी प्रतिबंध लगाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी नाबालिग के माता-पिता के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो अदालत माता-पिता के रूप में कदम उठाती है और तदनुसार नाबालिग के प्राकृतिक माता-पिता में पहले से दिए गए विवेक को अपने पास ले लेती है या जब्त कर लेती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रावधान का उल्लंघन पिता द्वारा किया गया है। ये प्रावधान एचएमजीएक्ट की धारा 2 में निहित स्पष्ट स्पष्टीकरण के मद्देनजर लागू होते रहेंगे।

9. एचएमजी अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट करती है कि यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो धर्म से हिंदू है और भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हिंदू कानून द्वारा शासित किया गया. वर्तमान मामले में, मां एक ईसाई हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने एचएमजी अधिनियम की प्रयोज्यता पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए हम मान लेंगे कि थलबीर हिंदू कानून द्वारा शासित है। यहां तक कि हमारे समक्ष कार्यवाही में भी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है कि एचएमजी अधिनियम पार्टियों के बीच काम नहीं करता है। एचएमजीएक्ट की धारा 6 मौलिक महत्व की है। यह धारा 4(बी) को दोहराता है और फिर से स्पष्ट करता है कि संरक्षकता व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति दोनों को कवर करती है; और फिर विवादास्पद रूप से कहा गया है

कि पिता और उसके बाद मां एक हिंदू के प्राकृतिक संरक्षक होंगे। ऐसा कहने के बाद, यह तुरंत प्रदान करता है कि 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा सामान्यतः मां के पास होगी। प्रावधान का महत्व और आयाम इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और बहुत संक्षेप में कहा गया है, एक प्रावधान एक अपवाद की प्रकृति में है जो पहले आम तौर पर निर्धारित किया गया है। "सामान्यतः" शब्द के प्रयोग पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। यह माँ के पक्ष में एक अनुमान लगाता है, भले ही खंडन योग्य हो। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने "आम तौर पर" शब्द के उपयोग के महत्व को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 13 में देखा है कि मदर ने थलबीर की अंतरिम हिरासत प्रदान करने के लिए अपनी उपयुक्तता स्थापित नहीं की है, जो उस समय थी। एक शिशु था. परंतुक यह साबित करने की जिम्मेदारी पिता पर डालता है कि नवजात बच्चे को उसकी मां की हिरासत में रखना उसके हित में नहीं है। संसद या विधानमंडल के विवेक को एक आकस्मिक व्याख्या द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तव में अधिनियम की भावना को समाप्त कर देता है।

10. अब हम अमेरिका में न्यायिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना में, सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा (2000) 3 एससीसी 14 में पिता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा हमारे सामने उद्धृत उदाहरणों की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। मां, सरिता, अपने वैवाहिक रिश्ते से दो बच्चों के साथ भारत लौट आई थीं। उच्च न्यायालय ने माना कि एक सक्षम न्यायालय से जारी तलाक की डिक्री और हिरासत के निर्देशों का सम्मान किया जाना चाहिए, और तदनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति दी और मां को बच्चों की हिरासत पिता सुशील को वापस करने का निर्देश दिया। यह न्यायालय इस बात से सहमत नहीं था कि भारत में न्यायालयों द्वारा इस बात पर आगे विचार किया जाए कि क्या बच्चों के हित, जो सर्वोपरि थे, पर रोक लगा दी जाएगी

और उन पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता है। एचएमजीएक्ट की धारा 6 के संबंध में, यह राय दी गई कि यद्यपि यह पिता को नाबालिग बेटे का प्राकृतिक अभिभावक बनाता है, लेकिन इसे नाबालिग के कल्याण के लिए अनुकूल क्या है, इसके सर्वोपरि विचार को खत्म करने वाला नहीं माना जा सकता है। इन टिप्पणियों को दोहराया गया और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि बच्चों के हितों और कल्याण के लिए यह तय है कि अभिरक्षा उनकी मां के पास होनी चाहिए। इसलिए, यह मामला उस कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति के विरुद्ध है जिसे पिता हमारे सामने रखना चाहते हैं। इस तथ्य को रेखांकित करना भी महत्वपूर्ण है कि दोनों बच्चे पांच वर्ष से अधिक उम्र के थे, एक किले, उच्च न्यायालय द्वारा मामले में मां से लेकर पिता तक की हिरासत को उलट नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि थलबीर तब लगभग एक वर्ष का था। और अभी भी तीन साल से कम है।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली, (2008) 7 एससीसी 673 की ओर आकर्षित किया है। इस मामले में भी, इस न्यायालय को 10 साल के लड़के को लेकर हिरासत संघर्ष का सामना करना पड़ा था। हमें यह बताने में शीघ्रता करनी चाहिए कि न्यायालय ने उन कारकों का विवरण देने के बाद एचएमजीएक्ट की धारा 6 पर विचार नहीं किया जो इस स्थिति का संकेत था कि बच्चे का कल्याण पिता के पास हिरासत जारी रखने में निहित है, इस न्यायालय ने मां की अपील खारिज कर दी। तथ्य पूरी तरह से भिन्न हैं। यह अनुपात जारी है कि नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि है।

12. एचएमजी एक्ट कहता है कि एक शिशु या एक नाजुक उम्र के बच्चे की अभिरक्षा उसकी मां को दी जानी चाहिए, जब तक कि पिता ऐसे ठोस कारणों का खुलासा नहीं करता है जो इस बात का संकेत देते हैं और अनुमान लगाते हैं कि अभिरक्षा बरकरार रखने पर बच्चे के कल्याण और हित की आजीविका कम हो जाएगी

या खतरे में पड़ जाएगी। मां द्वारा, एचएमजीएक्ट की धारा 6(ए), इसलिए, नाबालिग बच्चे की संपत्ति के संरक्षक होने के पिता के अधिकार को सुरक्षित रखती है, लेकिन उसके व्यक्ति के संरक्षक होने के अधिकार को नहीं, जबकि बच्चा पांच साल से कम उम्र का है। यह संरक्षकता के विपरीत, अंतरिम हिरासत के अपवाद को उजागर करता है, और फिर निर्दिष्ट करता है कि जब तक बच्चा पांच साल से कम उम्र का है तब तक हिरासत मां को दी जानी चाहिए। हमें तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि यह धारा या उस मामले में जी एंड डब्ल्यूएक्ट में शामिल कोई भी अन्य प्रावधान, पांच साल की उम्र पार करने के बाद भी मां को बच्चे की हिरासत के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है।

13. हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारा चिंतन उन पहलुओं तक ही सीमित होना चाहिए जो एक शिशु की अंतरिम हिरासत देने के लिए प्रासंगिक हैं। ट्रायल अभी भी लंबित है. आक्षेपित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर सही ढंग से ध्यान दिया है कि माँ एक स्थायी कॉलेज प्रोफेसर पद पर थीं, प्रसिद्ध हॉवर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर थीं और नियमित वेतन प्राप्त करती थीं। क्या उसका व्यक्तित्व द्वि-ध्रुवीय था जिसके कारण वह अपने नवजात बेटे थलबीर की अंतरिम अभिरक्षा के लिए अनुपयुक्त थी, यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ है। वर्तमान कार्यवाही के दौरान यह खुलासा हुआ कि पिता ने केवल हाईस्कूल पास किया है और स्नातक भी नहीं हैं। हमारे सामने इस बात से भी इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि वह नशीली दवाओं के पुनर्वास से गुजरा था और वह नारकोटिक्स एनोनिमस का सदस्य था। यह इस तथ्य से जटिल है कि वह नियमित रोजगार में नहीं है या उसकी स्वतंत्र आय नहीं है। आज की तारीख में वह आयकर निर्धारिती नहीं हैं, हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रति माह 40,000 से 50,000 रुपये कमाए हैं। हमें फिर से स्पष्ट करना चाहिए कि पिता की हिरासत की उपयुक्तता प्रासंगिक नहीं है जहां जिस बच्चे की हिरासत विवाद में है वह पांच साल से

कम है क्योंकि मां अपनी निविदा उम्र के दौरान शिशु की देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त है। चूंकि थलबीर पांच साल से कम उम्र का है, इसलिए यह पिता की जिम्मेदारी है कि वह मां की अनुपयुक्तता की वकालत करें और उसे साबित करें। इन विचारों में पिता का चरित्र और पृष्ठभूमि भी प्रासंगिक हो जाएगी, लेकिन केवल एक बार जब अदालत को माँ की उपयुक्तता पर दृढ़ता और दृढ़ता से संदेह हो; केवल तभी और तब भी माता-पिता की तुलनात्मक विशेषताएँ चलन में आएँगी। इस दृष्टिकोण को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं अपनाया गया है, जबकि इसे विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से अपनाया गया है।

14. हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक सामाजिक कार्यकर्ता के प्रावधान के तहत माँ को अस्थायी मुलाक़ात अधिकार प्रदान किए गए थे। हमें उनकी अत्यंत परिश्रमी और विस्तृत रिपोर्टों को पढ़ने का लाभ मिला है, जो थलबीर की अपनी मां के प्रति शुरुआती अनिच्छा और नापसंदगी को स्पष्ट रूप से बताती है, जो मां के मातृ स्नेह के कारण बहुत जल्दी स्वाभाविक हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वर्तमान में थलबीर अपनी माँ के साथ बेहद सहज और खुश है, लेकिन जब उसे अपने पिता के पास वापस लौटना होता है तो वह उसे देखकर उत्तेजित हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता ने यह भी आग्रह किया है कि उसकी रिपोर्ट को फादर के डर से सीलबंद रखा जाना चाहिए, यह हमारे लिए बेहद परेशान करने वाली बात है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि फादर के लिए भी ऐसा होना चाहिए।

2015 की सिविल अपील संख्या 1967

(एसएलपी से उत्पन्न © संख्या 32581/ 2014)

15. 2014 के डब्ल्यू पी 79 में विवादित आदेश पारित होने के बाद, माँ ने मुलाक़ात के अधिकार प्रदान करने के लिए दिनांक 20.08.2014 को एक आवेदन दायर किया। उनका सुझाव था कि उन्हें डोना पाउला, गोवा में सोमवार से शुक्रवार तक थलबीर की अभिरक्षा मिलनी चाहिए, जिसे शुक्रवार शाम 5.00 बजे पिता को लौटा दिया जाए; इसके बाद विचारण न्यायालय में सोमवार सुबह 10.00 बजे थलबीर की अभिरक्षा उसकी मां को सौंप दी जाएगी। पिता ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि उन्हें प्रत्येक सप्ताह में शाम 4.00 बजे के बीच लगातार तीन दिनों तक माँ के बच्चे से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। और शाम 5.00 बजे हालाँकि, उन्होंने दलील दी कि जून, 2013 से, वह थलबीर के साथ फ्लैट नंबर 2, आशीर्वाद बिल्डिंग, सिद्धि सदन कॉलोनी, बोरीवली पश्चिम, मुंबई में रह रहे थे। दिनांक 6.9.2014 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने आदेश दिया कि थलबीर को हर शनिवार सुबह 9.30 बजे अदालत में लाया जाना चाहिए। माँ को सौंप दिया जाएगा जो अगले सोमवार को शाम 5.00 बजे बच्चे को अदालत में पेश करेगी। यह वह आदेश है जिसे 2014 के डब्ल्यू पी नंबर 576 में चुनौती दी गई थी। दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश ने 'बारंबार' के अर्थ पर चर्चा की है, और निष्कर्ष निकाला है कि यह निरंतर नहीं हो सकता है; पिछले आदेश का मतलब यह नहीं हो सकता था कि थलबीर तीन दिनों के लिए विशेष रूप से अपनी माँ के साथ रहेगा। इस द्वंद्वात्मकता पर दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के दिनांक 6.9.2014 के आदेश में त्रुटि पाई। आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि माता का भारत में कोई स्थायी निवास नहीं है और उन्होंने गोवा में कोई निश्चित पता नहीं बताया था और माता द्वि-ध्रुवीय विकार से पीड़ित थीं। बेवजह, दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश ने सप्ताहांत में माता से मिलने के आदेश में गलती पाई, इस वास्तविकता को नजरअंदाज करते हुए कि विचारण न्यायालय केवल पिछले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू कर रहा था। यह हमारे लिए स्पष्ट

प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के लिए थलबीर के कल्याण के सवाल पर नए सिरे से विचार करना खुला नहीं था, जब मामला पिता के खिलाफ समाप्त हो गया था, जिन्होंने पिछले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी। विचारण न्यायालय से जो कुछ करने की अपेक्षा की गई थी वह माँ के लिए तीन दिन की हिरासत आवंटित करना था। वास्तव में दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के पिछले आदेश को अपनी समझ और अर्थ दिया है, जो हमें पिछली रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई बातों के बिल्कुल विपरीत लगता है। आदेश की व्याख्या करते हुए, आक्षेपित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर "अधिमानतः" शब्द जोड़ा है, लेकिन पिछले आदेश में "अधिमानतः" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। विवादित आदेश में इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है कि सभी तीन व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे और हाल ही में गोवा में स्थानांतरित हुए हैं, जो उस समय, पार्टियों का एकमात्र निवास स्थान था। इसमें मां के दावे को भी उचित महत्व नहीं दिया गया है कि उन्होंने अपनी बचत को गोवा के साथ-साथ मुंबई में संयुक्त नामों से संपत्ति खरीदने में निवेश किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिता संतोषजनक ढंग से यह दिखाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी कोई आय थी, प्रथम दृष्टया, माँ के बयान में विश्वसनीयता है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पिता ही थे जिन्होंने गोवा में कार्यवाही शुरू की थी, जिसके अधिकार क्षेत्र का माँ ने विरोध नहीं किया है और इसलिए, प्रारंभिक चरणों में माँ के खिलाफ रहना न तो उचित है और न ही उचित है। दोनों पक्षों के बीच पहले से चली आ रही लंबी मुकदमेबाजी को देखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुद्दों पर निर्णय नहीं लेने में लापरवाही बरती और इसके बजाय केवल 6.9.2014 के आदेश को रद्द कर दिया, जो

उनके समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए पेश किया गया था। पहले एक समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्देशों को रद्द कर दिया गया है और न्याय का हनन हो गया है।

16. 2014 की रिट याचिका 79 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि जब तक थलबीर की हिरासत पिता के पास जारी रहेगी, माँ को "मुलाकात के अधिकार" मिलेंगे, जिसे उन्होंने आपसी सहमति से सप्ताह में कम से कम तीन दिन अस्थायी रूप से तय किया था। अधिमानतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर, "गोवा में स्थित, मुकदमा गोवा में जारी है। हम 2014 की रिट याचिका 576 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए किसी भी कारण या औचित्य का पता लगाने या उसकी सराहना करने में विफल रहे, जो कि एक अलग विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2014 की एसएलपी (सी) 32581 से उत्पन्न 2015 की सिविल अपील का विषय है। हमने पहले ही जी एंड डब्ल्यूएक्ट की धारा 14 के इरादे को नोट कर लिया है जो नाबालिग से संबंधित संरक्षकता या हिरासत विवादों से निपटने में केवल एक अदालत की हितकारी आवश्यकता को स्वीकार करता है। इस याचिका में विद्वान सिविल जज द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.9.2014 के स्वामित्व को चुनौती दी गई थी, जो बदले में दिनांक 2.8.2014 के आदेश के अनुपालन में था, जिसे कम से कम तीन दिनों के लिए माँ से मिलने का अधिकार दिया गया था। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सप्ताह. पक्षों के अशांत विवाह के इतिहास, थलबीर की आईवीएफ अवधारणा आदि को प्रथम विद्वान एकल न्यायाधीश और विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा विधिवत नोट किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब गोवा राज्य में एचजीएम अधिनियम के साथ-साथ जी एंड डब्ल्यूएक्ट की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया था, एक ऐसा पहलू जिस पर पहले की किसी भी कार्यवाही में माता या पिता द्वारा उत्तेजित नहीं किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अदालत को हिरासत के विरोधाभासी दावों का सामना करना पड़ता है तो माता-पिता के कोई अधिकार नहीं होते हैं जिन्हें लागू करना पड़ता है;

बच्चा कोई वस्तु या गेंद नहीं है जिसे माता-पिता की ओर उछाला जाए। केवल बच्चे का कल्याण ही विचार का केन्द्र बिन्दु है। संसद का सही मानना है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः मां के पास होनी चाहिए और इस अपेक्षा से केवल मजबूत कारणों से ही इनकार किया जा सकता है। निर्णय में निरंतरता की आवश्यकता के कारण दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश को अपने विद्वान भाई के बजाय खुद को मामले से अलग करने के लिए राजी करना चाहिए था, जिन्होंने पिछली रिट याचिका पर फैसला किया था।

17. हम फादर द्वारा सिविल जज को सूचित किए बिना या अनुमति लिए बिना, थलबीर के साथ अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ने को भी गंभीरता से लेते हैं। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है और यह न्यायालय की अवमानना के समान भी हो सकता है। जी एंडडब्ल्यूएक्ट की धारा 26 का उल्लंघन किया गया है और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। स्थानांतरण अब एक सुविख्यात कानूनी अवधारणा है। चूँकि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य या यहाँ तक कि विश्व के एक देश से दूसरे देश में आना-जाना अब दुर्लभ नहीं रह गया है। अक्सर यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि बच्चे की देखरेख करने वाले माता-पिता को कहीं और अधिक उपयुक्त रोजगार मिल जाता है। इसलिए, पीछे छूट गए पति या पत्नी के अधिकार की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। माँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होना चाह सकती है जहाँ उसे पिता की तुलना में बहुत लाभप्रद रूप से नियोजित किया जा सकता है जो किसी भी आय या नियमित आय के स्रोत का खुलासा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमारे सामने ये मामला या स्टेज नहीं है. यहां, पिता ने गोवा में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़ने का विचार नहीं किया, जो माता-पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। ऐसा लगता है कि इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया और इसके बजाय विद्वान एकल

न्यायाधीश ने अनधिकृत स्थानांतरण को प्रीमियम दे दिया। हम पहले ही आपराधिक याचिका 87/2013 का उल्लेख कर चुके हैं जिसका निपटान माँ को थलबीर से मिलने की अनुमति देकर किया गया था; लेकिन गोवा में कार्यवाही की लंबितता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने गोवा में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश में हस्तक्षेप या परिवर्तन या संशोधित नहीं किया। फ़ोरम शॉपिंग या कोर्ट शॉपिंग से दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। दूसरे विद्वान एकल न्यायाधीश को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह पिता ही थे जिन्होंने गोवा में कार्यवाही शुरू की थी, जहां उस समय माता भी रह रही थीं, प्रथम दृष्टया, स्थिति में होने के लिए उन्हें कैलफोर्निया, यू.एस. में अपना रोजगार छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। अपने नवजात बेटे थलबीर की देखभाल के लिए। समन्वय पीठों को पूर्व आदेशों का सम्मान करना चाहिए।

18. हम आगे कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करेंगे क्योंकि मुकदमा अभी भी लंबित है। हमारे सामने सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम दिनांक 18.09.2014 के विवादित आदेश को रद्द करते हैं। यह समन्वित पीठ के पिछले आदेश के अनुरूप नहीं है और वास्तव में इसके मुख्य निर्देशों को गंभीर रूप से रद्द कर देता है। हमने 2 अगस्त, 2014 के आक्षेपित आदेश को अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से रद्द कर दिया कि यह शिशु थलबीर की अस्थायी हिरासत के लिए उपयुक्तता दिखाने के लिए मां पर गलत तरीके से बोझ डालता है और इसलिए, एचएमजी अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। हम स्पष्ट करते हैं कि पिता द्वारा प्रस्तुत या रिकॉर्ड पर रखी गई कोई भी बात यह नहीं बताती है कि माँ शिशु थलबीर की देखभाल करने में इतनी अयोग्य है कि यह एचएमजीएक्ट की धारा 6 में वैधानिक धारणा से विचलन को उचित ठहराती है। संक्षेप में बताए गए मुलाक़ात अधिकार हिरासत या अंतरिम हिरासत आदेशों से अलग हैं। अनिवार्य रूप से वे उस माता-पिता को सक्षम बनाते हैं जिनके पास अंतरिम हिरासत नहीं है, ताकि वे बच्चे को

दूसरे माता-पिता की हिरासत से हटाए बिना उससे मिल सकें। यदि किसी बच्चे को माता-पिता से कई घंटे या यहां तक कि कई दिन दूर रहने की अनुमति दी जाती है, जिसे न्यायालय द्वारा हिरासत दी गई है, तो बच्चे की अस्थायी हिरासत अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाती है।

19. हमने सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई रिपोर्टों पर भी उचित ध्यान दिया है और इस संबंध में पार्टियों के वकील को सुना है। हम उस परिश्रम के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं जिसके साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। यदि पिता द्वारा उसकी फीस/खर्च का भुगतान नहीं किया गया है, तो शेष राशि का भुगतान महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

20. हम थलबीर की अस्थायी हिरासत ई अपीलकर्ता/माँ को इस निर्देश के साथ हस्तांतरित करते हैं कि वे दोनों उसके द्वारा दिए गए पते पर रहेंगे, जैसे, हाउस नंबर 80, मैगनोलिया, ग्राउंड फ्लोर, बिन वाड्डो, बेतालबाटीम, गोवा और बिना पूर्व अनुमति के विचारण न्यायालय के उस क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को नहीं छोड़ेंगे। हम आगे निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी/पिता को दोपहर 2.30 बजे के बीच मुलाक़ात का अधिकार होगा। और शाम 6.00 बजे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को और शनिवार को दोपहर 2.30 बजे से रात 9.00 बजे तक। ये आदेश पूर्णतः अस्थायी प्रकृति के हैं। सिविल जज को अपने समक्ष लंबित याचिका/आवेदन पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्रता से निर्णय करना चाहिए, ऊपर हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना।

21. सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती दीपाली अजय सातपुते की रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ने के बाद, हमें श्री अरुण शर्मा, पिता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के किसी भी सदस्य या अपने दोस्तों के माध्यम से किसी भी तरीके से संवाद करने या सामाजिक कार्यकर्ता से मिलने का निर्देश देना आवश्यक लगता है। श्रीमती दीपाली

अजय सातपुते. यह उन आशंकाओं के संदर्भ में है जो उसने प्रतिवादी और उसकी मां की उसके साथ-साथ उसके अपने बेटे की सुरक्षा के संबंध में बातचीत के परिणामस्वरूप महसूस की और अदालत के सामने व्यक्त की। यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने और अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करती है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस अधिकारी तुरंत इसे प्रदान करेगा और हम ऐसा निर्देश देते हैं।

22. इन शर्तों में अपील की अनुमति है। पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगी।

निधि जैन अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।